



Neutral Citation No. - 2026:AHC:60167

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 7980 वर्ष 2026

शिवम उर्फ कालू

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मुकेश चंद्र गुप्ता, शुभम प्रकाश गुप्ता

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा

- हमने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री शुभम प्रकाश गुप्ता की बात सुनी, और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान एजीए श्री बी.पी. मौर्य की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत वर्तमान जमानत याचिका आवेदक की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें प्रकरण अपराध संख्या 104/2024 में, धारा 352, 307, 120-बी, 34 भारतीय दंड संहिता और धारा 3/25/27 शस्त्र अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन सदर

"अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बाजार, जिला मेरठ में दर्ज मामले में मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह भी निवेदन किया गया है कि आवेदक का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं है। यह भी निवेदन किया गया है कि पीड़ित ने अपने बयान में यह भी कहा है कि लंबे बालों वाले एक व्यक्ति ने उस पर बंदूक से हमला किया था और उसने आवेदक की पहचान की थी, जब जांच अधिकारी ने उसे तस्वीर दिखाई थी। यह भी निवेदन किया गया है कि जांच अधिकारी द्वारा पहचान परेड आयोजित की गई है। आवेदक, जो 10.06.2024 से जेल में बंद है, वचन देता है कि यदि उसे आजादी दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में मामलों की भारी संख्या में लंबितता के कारण, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है और उन्होंने यह प्रस्तुत किया है कि घायल ने जांच के दौरान आवेदक की स्पष्ट रूप से पहचान की है।

5. अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है और जांच के दौरान आवेदक का नाम सामने आया है। घायल ने बताया है कि लंबे बालों वाले एक व्यक्ति ने उस पर बंदूक से हमला किया था और उसने आवेदक की पहचान की थी, जब जांच अधिकारी ने उसे आवेदक की तस्वीर दिखाई थी। कोई पहचान परेड आयोजित नहीं की गई है। घायल की चोट रिपोर्ट के अनुसार, उसके चेहरे पर बंदूक की गोली से चोट के निशान पाए गए हैं। आवेदक 10.06.2024 से जेल में बंद है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



6. सभी तथ्यों, प्रकृति और अभिलेख से प्राप्त साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

7. उपर्युक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ता **शिवम उर्फ कालू** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार जमानत पर रिहा किया जाएगा।

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, (ii) आरोप तय होने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा जब गवाह विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



8. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य से है और इसे किसी भी तरह से मामले की योग्यता पर टिप्पणी के रूप में नहीं माना जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होगा।

24 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जीतेन्द्र कुमार सिन्हा)

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”